

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 27 मई, 2008

विषय: पाईन्स, नैनीताल स्थित मा० उच्च न्यायालय के स्टाफ क्वार्टर्स में जल संयोजन के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-947/यूएचसी/एडमिन.बी/निर्माण/2008, दिनांक 17.3.08 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पाईन्स, नैनीताल स्थित मा० उच्च न्यायालय के स्टाफ क्वार्टर्स में जल संयोजन के कार्य हेतु रु० 21,36,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 18,38,000/- (अठारह लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु० 18,38,000/- (अठारह लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाय ।
- (3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकृत विभाग/सक्षम अधिकारी से नक्शा पास कराया जाना आवश्यक है ।
- (4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।
- (5) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।
- (6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।
- (8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
  - (10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
  - (11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
  - (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।
4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-19पी/XXVII(5)/2008, दिनांक 08.5.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

( आर०डी०पालीवाल )

सचिव ।

संख्या-08-दो(8)/XXXVI(1)(2)/08-16-दो(2)/05-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
5. अधिशाली अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, शाखा नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( आलोक कुमार वर्मा )

अपर सचिव ।